भूकम्प के बाद गुजरात

प्रकाश लुईस

गुजरात में भूकम्प ने हज़ारों लोगों की जान ले ली; बहुत तो अभी भी गिनती में शामिल नहीं हो सके हैं। सेना और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने ही बचाव और राहत कार्यों की पहल की थी लेकिन पुनर्निर्माण की भारी ज़िम्मेदारी अब सरकार पर आन पड़ी है। एक स्थाई सुदृढ़ भविष्य के पुनर्निर्माण के इस कार्य को जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करना होगा।

गुजरात, खासकर इसके कच्छ क्षेत्र में जो भूकम्प आया वह अपने पीछे बरबादी तथा मौत का आलम छोड़ गया है। इसने 70 प्रतिशत से ज़्यादा रिहायशी इलाकों को ज़मींदोज़ कर दिया। राहत और पुनर्वास की धीमी तथा सुस्त प्रक्रिया ने भुक्तभोगियों के मन में इस भय को और गहरा ही किया है कि उनके दुखों का अन्त अभी भी नहीं हुआ है। आम समय में तो जातिगत आधार पर होने वाले दुरावों तथा सामाजिक भेदभावों को सामान्य चलन मान लिया जाता है लेकिन आपदा के वक्त भी सामाजिक तथा धार्मिक भेदभाव का क्रूर चेहरा सामने आया है।

1991 की जनगणना के अनुसार गुजरात की जनसंख्या लगभग 4.13 करोड़ थी। यह दुखद तथ्य है कि मुख्यतः अल्प और गलत बचाव व राहत कार्यों के चलते भूकम्प प्रभावित पांच ज़िलों में इसकी मार को सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी ने ही झेला है।

सबसे असहाय तबका

यहां पर जनसंख्या के उन असुरक्षित व असहाय वर्गों पर नज़र डालना सामयिक होगा जो सरकारी तंत्र की राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी और कुछ राहतकर्मियों के जातिगत भेदभाव की वजह से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे। भूकम्प प्रभावित ज़िलों में अनुसूचित जाति अथवा दलितों की जनसंख्या राज्य औसत से ज़्यादा है।

भूकम्प के केन्द्र कच्छ में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहां आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों की आबादी भी बहुत है। कच्छ में दलितों की संख्या